भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4112
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: उच्च मूल्य वाली फसल का विविधीकरण

4112. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंद्रू बारणेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट 2026-27 में कृषि के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान "विकसित भारत" के दृष्टिकोण के तहत उच्च मूल्य वाली फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है;

(ख) क्या अखरोट, चंदन और नारियल जैसी फसलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित किसानों की आय में वृद्धि करना और देश की कृषि-निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ करना है;

(ग) क्या समर्पित नारियल संवर्धन योजना और वृक्षारोपण पुनरुद्धार उपायों से बागान क्षेत्र में उत्पादकता और स्थायित्व में सुधार होने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में 1.70 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी से, उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण के लिए बदलाव के दौरान आदान-लागत में स्थिरता सुनिश्चित होती है; और

(ङ) क्या इन संयुक्त उपायों से किसानों की दीर्घकालिक आय संभावनाओं में सुधार करते हुए खाद्य सुरक्षा और निर्यात वृद्धि का संतुलन बनाया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) बजट 2026-27 में कृषि के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन "विकसित भारत" की परिकल्पना के अंतर्गत उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने की एक व्यापक कार्यनीति को दर्शाता है, क्योंकि उक्त बजट कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है तथा तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों, पूर्वोतर में अगर के वृक्षों और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और चीड़ के मेवों जैसी फसलों के लिए सहायता देता है।

(ग): नारियल संवर्धन योजना और बागान पुनरूद्धार उपायों से बागान क्षेत्र में उत्पादकता और सततता में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि नारियल संवर्धन योजना का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, पुनःरोपण और पुनरूद्धार, क्षेत्र विस्तार, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पद्धतियों, मूल्यवर्धन और नारियल में निर्यात संवर्धन के माध्यम से नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल क्षेत्र का पुनरूद्धार करना है।

(घ): 1.70 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी विविधीकृत उच्च मूल्य वाली कृषि की ओर अभिमुख होने के दौरान, इनपुट लागत स्थिरता सुनिश्चित करती है, क्योंकि यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 2018 से अपरिवर्तित रहा है और वर्तमान में 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग है। इसी प्रकार, डीएपी की एमआरपी 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग है, जो पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान स्थिर रही है। ये उपाय किसानों को उर्वरकों की मूल्य स्थिरता और उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है और उच्च मूल्य वाली कृषि की ओर विविधीकरण को सुगम बनाया जा सकता है।

(ङ): ये संयुक्त उपाय किसानों की दीर्घकालिक आय संभावनाओं में सुधार करते हुए खाद्य सुरक्षा और निर्यात वृद्धि के बीच संतुलन बनाते हैं।

*****